व्यापार

केंद्र सरकार इलाहाबाद बैंक में डालेगी 3,054 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। सरकारी बैंक इलाहाबाद बैंक ने कहा है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में बैंक में 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। बयान में कहा गया है कि सरकार ने बैंक को सूचना दी है कि वह वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी इक्विटी शेयरों (विशेष सिक्युरिटी/बांड्स) के तरजीही आवंटन के बदले निवेश के रूप में डालेगी। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत में इलाहाबाद बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-3 नियमन के मुताबिक 6.88 फीसद रह गई थी, और इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 71.81 फीसद थी। बैंक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1,944.37 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में बैंक को 28.84 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोलकाता स्थित मुख्यालय वाले इस बैंक पर इस साल मई में शीघ्र सुधार कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत अतिरिक्त पाबंदी लगाई थी।

एमजंक्शन से लघु उद्योगों को बिक्री बढ़ाएगी टाटा स्टील

कोलकाता, 9 नवम्बर (ए)। कंपनियों को अपास में खरीद फरोख्त का आन-लाइन मंत्र उपलब्ध कराने वाली कंपनी एमजंक्शन सर्विसेस लिमिटेड ने इस मंच के माध्यम से टाटा स्टील का प्राथमिक इस्पात खरीदने के लिए लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को कर्ज उलब्ध कराने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। एमजंक्शन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय वर्मा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि इस कार्यक्रम का नाम 'ऊर्जा' है। इसके तहत टाटा स्टील के वितरकों से सामग्री खरीदने वाले खरीदारों को बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। वर्मा ने कहा, ''हम प्राथमिक इस्पात खरीदने वाले एक श्रेणी के एमएसएमएमई ग्राहकों को को यह सेवाएं देंगे ।अब इस मंच पर एमएसएमई को बिना नकद खर्च किए इस्पात खरीदने की सुविधा होगी जो पारंपरिक तरीके से संभव नहीं है।''उन्होंने कहा, ''इसके लिए वित्त की व्यवस्था टाटा स्टील नहीं करेगा। हमारे पास वित्त देने वाली कंपनियां हैं जो टाटा स्टील के उत्पादों की खरीद के लिए कर्ज देंगी।'' एमजंक्शन ने कहा कि टाटा कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प और एक्सिस बैंक पहले ही उसके मंच पर वित्त की सुविधा दे रहे हैं। अभी आदित्य बिड़ला फाइनेंस के साथ बातचीत जारी है।

फोर्टिस के सीईओ भवदीप सिंह ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (एफएचएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भवदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एफएचएल ने गुरुवार को कहा कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि सिंह ने गुरुवार को ही इस्तीफा दिया और कंपनी के निदेशक बोर्ड ने उसे स्वीकार कर लिया। हालांकि बोर्ड ने सिंह से अगले सीईओ की नियुक्ति तक पद पर बने रहने का आग्रह किया, जिसे सिंह ने मान लिया। भवदीप सिंह पिछले साढ़े तीन वर्षों से फोर्टिस हेल्थकेयर से जुड़े हुए हैं। कंपनी ने कहा कि सिंह ने पिछले बेहद चुनौतीपूर्ण दो वर्षों के दौरान फोर्टिस का बेहद कुशलता से नेतृत्व किया। गौरतलब है कि सिंह ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है, जब इसी वर्ष जुलाई में मलेशिया की आइएचएच हेल्थकेयर ने फोर्टिस हेल्थकेयर चेन का अधिग्रहण कर लिया था। आर्थिक तंगी से जूझ रही फोर्टिस में आइएचएच ने प्रेफरेंशियल शेयर आवंटन के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये पूंजी निवेश का वादा किया।

रॉबिन डेनहोम होंगी टेस्ला की चेयरपर्सन

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। एलन मस्क के टेस्ला के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद कंपनी ने कहा कि उसने रॉबिन डेनहोम को चेयरपर्सन नियुक्त किया है। डेनहोम अभी ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेलस्ट्रा की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हैं। टेस्ला ने बुधवार को एक बयान में कहा कि नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू है, लेकिन डेनहोम अपनी वर्तमान कंपनी में छह महीने के नोटिस पीरियड दौरान काम करती रहेंगी। डेनहोम इससे पहले भी 2014 से टेस्ला के निदेशक बोर्ड की सदस्य रह चुकी हैं। मस्क ने अक्टूबर में टेस्ला के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने एक ट्वीट से पैदा हुए धोखाधड़ी के आरोपों का निपटारा करने के लिए अमेरिकी नियामक के साथ एक समझौते के तहत यह इस्तीफा दिया है। अपने विवादित ट्वीट में मस्क ने कहा था कि वह कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शेयर खरीदने वालों का इंतजाम कर लिया है। इस सेटलमेंट के तहत कंपनी और मस्क दोनों को दो करोड़ डॉलर (प्रत्येक) देना पड़ा, लेकिन मस्क को कंपनी का सीईओ रहने दिया गया।

सरकार ने आरबीआई से नहीं मांगे 3.6 लाख करोड़ रुपए : आर्थिक मामलों के सचिव

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से 3.6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की कोई मांग नहीं कर रही है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को किए एक ट्वीट में कहा कि आरबीआई से उसके सरप्लस की मांग करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में चल रही उन अटकलों को खारिज किया कि सरकार एक लाख रुपए से लेकर 3.6 लाख करोड़ रुपए तक लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का राजकोषीय हिसाब-किताब बिल्कुल सही चल रहा है। गर्ग ने कहा कि सराकर केवल केंद्रीय बैंक की आर्थिक पूंजी व्यवस्था तय करने के बारे में चर्चा कर रही है। आर्थिक मामलों के सचिव ने विश्वास जताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने के बजट में तय लक्ष्य के भीतर बनाए रखने में कामयाब होगी। सरकार का राजकोषीय हिसाब-किताब ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के बराबर था। उसके बाद से सरकार इसमें लगातार कमी करती आ रही है। हम वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में राजकोषय घाटे को 3.3 तक सीमित कर देंगे।

बताते चलें कि सरकार और आरबीआई के बीच कई मामलों को लेकर विवाद चल रहै है, जिसमें रिजर्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि सरकारी बैंकों के कैपिटल और लैंडिंग के अंतर को आसान किया जाए। बीते कुछ हफ्तों में यह विवाद काफी बढ़ गया है और 19 नवंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इसे उठाया जाएगा।

सरकार बेचेगी विभाजन के बाद पाकिस्तान गए निवेशकों के शेयर

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। सरकार ने एक अहम फैसले में विनिवेश प्रक्रिया के तहत 6.5 करोड़ से ज्यादा 'एनिमी शेयर' की बिक्री के लिए तैयार किए गए मैकेनिज्म को मंजूरी दे दी। ये शेयर भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए निवेशकों के हैं। सरकार को 996 कंपनियों में इन शेयरों की बिक्री से उनके मौजूदा मूल्य पर करीब 3,000 करोड़ रुपये हासिल होने की उम्मीद है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रम डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्ण विनिवेश समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक के बाद एक बयान में सरकार ने कहा कि दशकों से यूं ही पड़े एनिमी शेयरों की बिक्री से हासिल रकम को विकास कार्यों में लगाया जाएगा। बयान के मुताबिक गृह मंत्रलय/कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया (सीईपीआइ) के पास 996 कंपनियों में 20,323 शेयरधारकों के 6,50,75,877 शेयर पड़े हुए हैं। इनमें 588 कंपनियां इस वक्त चल रही हैं और 139 कंपनियां सूचीबद्ध भी हैं। इन शेयरों की बिक्री से संबंधित अनुमोदन एक वैकल्पिक तंत्र या ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म देता है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले इस तंत्र में गृह मंत्री और सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री शामिल हैं।

बैंकों में सुधार के संकेत, लेकिन बुनियादी आधार अभी भी कमजोर: रपट

सिंगापुर, 9 नवम्बर (ए)। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संकेत दिख रहे हैं लेकिन बुनियादी आधार अभी भी कमजोर बना हुआ है और इसे 'स्वस्थ स्तर' पर आने में लंबा वक्त लगेगा। डीबीएस ने शुक्रवार को अपनी एक रपट में यह बात कही। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी डीबीएस के अनुसार हालिया दो तिमाही में भारतीय बैंकों की आय में सुधार के संकेत दिखे हैं। उनकी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता भी हल्की बेहतर हुई है।

रपट में कहा गया है कि अधिकतर बैंकों का सकल गैर-निष्पादित कर्ज (एनपीएल) कम हुआ है और नया गैर-निष्पादित कर्ज कम बढ़ा है। कुछ बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता आने वाली तिमाहियों में और बेहतर होने की भी संभावना है। जून-सितंबर तिमाही में देश के दो प्रमुख बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक फिर से लाभ की स्थिति में आए हैं। जबकि इससे पहली तिमाहियों में वे नुकसान में थे। कर्ज की कम लागत से बैंकों के मुनाफे को समर्थन मिला है। डीबीएस ने अपनी शोध रपट में कहा, ''हमारे नमूनों में सकल एनपीएल का अनुपात 10 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है जबकि उनका पूंजीकरण सिर्फ पर्याप्त स्तर पर बना हुआ है।''हमारा अनुमान है कि सरकार समय-समय पर इक्विटी के माध्यम से पैसा डालकर बैंकों में पूंजी के स्तर को बनाए रखेगी।

अमेरिका को पीछे छोड़ स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना भारत

नयी दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। इस साल जुलाई से सितंबर की तिमाही में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया. शोध कंपनी कैनालिस के एक रपट में यह दावा किया गया है. रपट के आंकड़ों के मुताबिक साल की तीसरी तिमाही में भारत में 4.04 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई. वहीं 10.06 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री के साथ चीन पहले स्थान पर रहा. अमेरिका में इस अवधि में चार करोड़ स्मार्टफोन बिके. कैनालिस ने कहा कि जुलाई-सितंबर, 2018 के दौरान दुनियाभर में सालाना आधार पर स्मार्टफोन की बिक्री में 7.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी. इस अवधि में दुनिया भर में 34.89 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई. कंपनी की रपट में कहा गया है कि यह लगातार चौथा साल है, जब स्मार्टफोन की बिक्री में कमी आयी है.

सरकार ने 6 एयरपोर्ट को लीज़ पर देने के लिए मंजूरी दी

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत लीज़ पर दिए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मेंगलुरु हवाई अड्डों के लिए ये अहम फैसला सुनाया।

पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया जायेगा। सरकार की ओर से एक आधिकारिक ट्वीट में कहा गया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले इन हवाई अड्डों का प्रबंधन पीपीपी के तहत किया जाएगा। ट्वीट में कहा गया है कि पीपीपीएसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी मुद्दे को निपटाने के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, पीपीपी मॉडल के तहत प्रबंध किए जा रहे हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि शामिल हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए पीपीपी मॉडल से बुनियादी ढांचा परियोजना में हवाई अड्डों पर विश्व श्रेणी का बुनियादी ढांचा जुटाने, हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कुशल और समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति करने और बिना किसी निवेश के भारतीय विमान प्राधिकरण की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने में मदद मिली है। भारत में पीपीपी हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) के रूप में हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में रैंक हासिल की है।

अब मुजफ्फरपुर और कोडरमा में भी शुरू होगी सीएनजी-पीएनजी सेवा, देश के 50 शहरों के लिए मिलेगा लाइसेंस

नयी दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। अब बिहार-झारखंड के शहरों में भी बड़े शहरों की तर्ज पर सीएनजी से गाड़ियां चलेंगी और लोगों के किचन में पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध होगी. तेल नियामक पीएनजीआरबी ने बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, खड़गिया, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर और नवादा जिले में इस सुविधा के लिए जल्द निविदा जारी करेगी, जबकि झारखंड के कोडरमा और देवघर में यह सुविधा हासिल होगी.

निविदा के 10वें दौर में बिहार-झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, हरियाणा के कैथल, कर्नाटक के मैसूर और गुलबर्ग, केरल के अल्लापुझा और कोल्लम, मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना, उत्तर प्रदेश के झांसी और बस्ती, पंजाब के फिरोजपुर और होशियारपुर, राजस्थान के अजमेर और जालौर, उत्तराखंड के नैनीताल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं हावड़ा सहित 50 शहरों में लाइसेंस देने की योजना है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की निविदाओं का यह 10वां दौर है. इसमें 12 राज्यों में पड़ोसी जिलों को सम्मिलित करते हुए 50 भौगोलिक इलाकों में सीएनजी/पीएनजी के खुदरा वितरण के लिए लाइसेंस दिये जायेंगे. निविदा जमा कराने की अंतिम तारीख 5 फरवरी है. निविदा भरने वालों को यह बताना होगा कि वे आठ साल में संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में कितने सीएनजी स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं और कितने घरों तक पाइप से गैस पहुचाने की उनकी योजना है. उन्हें क्षेत्र में बिछायी जाने वाली पाइपलाइन की अनुमानित लंबाई भी बतानी होगी.

भारत के साथ फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाना चाहते हैं यूरोपीय देश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (ए)। भारत द्वारा ब्रिटेन और जर्मनी के लिए स्थापित फास्ट ट्रैक सिस्टम की सफलता को देखते हुए कई और यूरोपीय देशों ने इस नई व्यवस्था में रुचि दिखाई है। यह व्यवस्था भारत में कारोबार वाली कंपनियों और निवेशकों की समस्याओं की पहचान और निराकरण में मदद करती है। भारत ने ब्रिटेन और जर्मनी के साथ इस तरह की व्यवस्था स्थापित की हुई है। इन दोनों देशों के लिए भारत का फास्ट ट्रैक सिस्टम अलग-अलग है। इटली और हॉलैंड के साथ भी इस सिस्टम को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। ये यूरोपीय देश भी अपने यहां इसी तरह की प्रणाली स्थापित करेंगे, ताकि इन देशों में निवेश वाली भारतीय कंपनियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। एक अधिकारी ने कहा कि इस सिस्टम की सफलता को देखते हुए, अब हमें भारत में बड़े निवेश वाले अन्य यूरोपीय देशों से भी इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनुरोध मिल रहे हैं। यह सिस्टम भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय तथा संबंधित देशों के समकक्ष विभागों में स्थापित किया जाता है।

बेहिसाबी अर्थव्यवस्था को कम करने में सफल रही नोटबंदी: मेघवाल

जयपुर, 9 नवम्बर (ए)। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को यहां कहा कि मोदी सरकार की नोटबंदी अपने मूल उद्देश्य में सफल रही और इससे देश की बेहिसाबी अर्थव्यवस्था (शेडो इकनामी) में भारी कमी आई।

नोटबंदी के दो साल पूरे होने पर यहां संवाददाताओं से बातचीत में मेघवाल ने कहा, ''मूल उद्देश्य था देश में शेडो अर्थव्यवस्था को घटाना और इसमें नोटबंदी एक सफल उपाय साबित हुआ। भीम एप, यूपीआई ये आंकड़े इसके गवाह हैं कि हम कितनी तेजी से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े हैं।'' विश्व बैंक की एक रपट के हवाले से उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी हुई उस समय इस देश में शेडो इकनामी 23.7 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा, ''किसी भी विकसित देश में ऐसा आंकड़ा नहीं था। यह इकनामी,आर्थिक गतिविधि तो है लेकिन जीडीपी में इसकी गणना नहीं होती। शेडो इकनामी देश में अपराध बढ़ा रही थी, काले धन को बढ़ा रही थी और कर संग्रहण को भी प्रभावित कर रही थी। डिजिटल लेनदेन भी बड़ा मुद्दा था।'' उन्होंने आगे कहा, ''मनमोहन सिंह के कालखंड में भी यह विषय था। लेकिन वह इस पर कोई निर्णय नहीं कर पाए क्योंकि वह हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि वह अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसमें दो बड़े प्रयास नोटबंदी व जीएसटी थे। उन्होंने कहा, ''डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने से शेडो इकनामी को चोट पहुंची। हम अगर इसे 15 या 14, 13 प्रतिशत तक ले जाते हैं तो यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है।' इस अवसर पर उन्होंने व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत के 143वें पायदान से 77वें पायदान पर आने तथा कर संग्रहण के एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने जैसी उपलब्धियों का भी जिक्र किया।